स्कूलों की सबसे ज्यादा संख्या कर्नाटक में है। सर्वे पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक बिना छात्रों वाले स्कूलों में 15,791 primary और बाकी secondary एवं Higher Secondery स्कूल हैं। सर्वे रिपोर्ट फिर कहती है कि 25 से भी कम छात्रों वाले स्कूल लगभग 70 हजार हैं,जबकि 1 लाख 70 हजार स्कूल ऐसे हैं,जिनमें केवल 26 से 50 छात्र हैं। छात्र न होने की वजह यह है कि यातो वहां कोई टीचर नहीं है और यदि है तो वह स्थायी नहीं है। 23 हजार स्कूल ऐसे भी हैं जहां अध्यापक भेजा जाना बाकी हैं। 1 लाख 30 हजार स्कूल ऐसे हैं,जहां सिर्फ एक ही टीचर हैं।

क्या सरकार संबद्व शिक्षा विभागों के निर्देशकों को स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं और पर्याप्त टीचर मुहैया कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगी,ताकि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित हों।

Need to take measures to remove obstacles in the development of Science and Technology in the country

श्री जय प्रकाश अग्रवाल(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली)**:** उपसभापति जी,मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उन समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं,जो भारतीय विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी के विकास में बाधक बनी हुई हैं। IBM India Reseaech Lab,जो दिल्ली में है और जो softwares के क्षेत्र में अपने ग्राहकों को softwares के अत्याधुनिक एंव सभी प्रकार के निष्कर्ष प्रदान करती है,मैं भी वैज्ञानिकों की भारी कमी है। इसी प्रकार से अन्य कई प्रयोगशालाएं भी वैज्ञानिकों की कमी का सामना कर रही है। विज्ञान के अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय हिस्सेदारी काफी प्रभावित हो रही है।

द्वितीय,नेनोटैक्नोलोजी उद्योग ने दावा किया था कि वे देश के हर क्षेत्र में-रक्षा से स्वास्थ्य तक के सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे,किंतु खेद है कि ज्यादातार उद्योगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस नेनोटैक्नोलोजी में शुरूआत के धन को लगाने में कोई भी निवेशक निवेश करने को तैयार नहीं है। इन उद्योगों में निवेशकों को लगता है कि कहीं उनका धन डूब न जाए क्योंकि नेनोटैक्नोलोजी उद्योगों के विकास एंव वाणिज्यकरण में एक लंगा समय लगता है।

तीसरा,National Innovation Foundation, जो कि अपनी संस्थाओं के माध्यम से नवीन पद्वति को निम्न स्तर से उठकर मजबूती प्रदान करता हैं,इनके छोटे पैमाने के आविष्कारों का सामाजिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की कार्य प्रणाली एंव उत्पादानों को पंजीकृत करवाकर उन्हें बाजारों में भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए,परन्तु ऐसा कुछ नहीं हो रहा हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक पहल करे।

Demand to streamline the Crop Insurance Scheme

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Sir, through this Special Mention, I wish to point out the bizarre working of the Crop Insurance Scheme which is designed to provide succour to the farmers who got in the debt trap.

In Ambejogai tehsil of Beed district of the Monarch Rod region of Maharashtra,